

**THE
PARLIAMENTARY DEBATES
OFFICIAL REPORT**

IN THE THIRTY-SEVENTH SESSION OF THE RAJYA SABHA

*Commencing on the 12th March, 1962/the 21st Phalguna,
1883 (Saka)*

1

RAJYA SABHA

*Monday, the 12th March, 1962/the 21st
Phalguna, 1883 (Saka)*

The House met at half past twelve of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

MEMBER SWORN

Shri Muhammad Ishaque (West Bengal)

**PRESIDENT'S ADDRESS LAID ON
THE TABLE**

SECRETARY: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 12th March, 1962.

*(Text of the President's Address in
Hindi)*

संसद् के सदस्यगण, आपके सम्मुख इस संसद् में कुछ कहने का मेरे लिये यह अन्तिम अवसर है ।

लोक सभा के सदस्यगण, इस सदन की आपकी सदस्यता की पंचवर्षीय अवधि अब समाप्त होने को है । शीघ्र ही आपके इस सत्र की समाप्ति के बाद नयी लोक सभा की बैठक होगी । आप में से बहुतों को देश सेवा के लिये फिर मे चुन लिया गया है । आपमें से कुछ इस चुनाव तथा लोक सभा की समाप्ति के बाद नयी लोक सभा के सदस्य नहीं रहेंगे । मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ और लोक सभा के सदस्यों की हैसियत से आपके द्वारा की गई सेवाओं के लिये देश की जनता

2

की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि यहां से जाने के बाद जहां भी आपका कार्यक्षेत्र हो, आप देशनिर्माण के काम में लगे रहेंगे और अपनी योग्यता तथा अनुभव का सदा ही अपने देश की जनता के हितार्थ उपयोग करते रहेंगे ।

संसद् के सदस्यगण, जब मैंने पिछली बार आपको सम्बोधित किया था, तब अपने अधिक व्यापक दृष्टिकोण तथा उच्चतर लक्ष्य के साथ हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी । अब वह योजना चालू की जा चुकी है । पहली योजनाओं से प्राप्त अनुभव और उससे उत्पन्न हुए उत्साह और राष्ट्रनिर्माण के काम में योजनागत प्रयास के सम्बन्ध में अधिक देशव्यापी बोध और अधिमूल्यन—ये सब बातें इस योजना की सफलता की द्योतक हैं और हमें अपने निर्धारित उद्देश्य के निकट ले जाने वाली हैं । हमारा उद्देश्य ऐसी समर्थ अर्थ-व्यवस्था की प्राप्ति है, जिसमें स्वावलम्बन, अभिवृद्धि और अधिक भावी विकास के साधनों को पैदा करने की क्षमता हो ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास तथा केरल में बाढ़ों द्वारा जो भारी नुकसान हुआ, उसके बावजूद १९६१-६२ में होने वाली खेती की पैदावार उत्साहवर्द्धक है । हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती की उन्नति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ।

हमारा उद्देश्य केवल अनाज में आत्मनिर्भर होना ही नहीं है, बल्कि निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा संग्रह करने तथा बढ़ते हुए उद्योगों के लिये कच्चा माल उपलब्ध करने के लिये व्यापारी पैदावार को बढ़ाना भी है।

१९६०-६१ में खेती उत्पादन का इण्डेक्स नम्बर १३६.१ हो गया है जबकि १९५६-६० में वह १२८.७ था। इस तरह इसमें ८.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में दोनों फसलों का अनाज तथा व्यापारी हिस्सा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष १९५५-५६ था और उस वर्ष के इण्डेक्स की तुलना में १९६०-६१ उत्पादन की इण्डेक्स १६.१ प्रतिशत अधिक है।

भूमि के संरक्षण सम्बन्धी उपायों और सूखी खेती के साधनों को अपनाने के फलस्वरूप तीन करोड़ तीस लाख एकड़ भूमि में सुधार होगा। सिंचाई की छोटी योजनाओं से एक करोड़ अठाईस लाख एकड़ भूमि तीसरी योजना में खेती के योग्य बन सकेगी। मेरी सरकार ने एक उन्नत बीज निगम स्थापित करने का निश्चय किया है, जो अधिक उत्पादन देने वाले और बीमारी का प्रतिरोध करने वाले बीजों के वितरण और बिक्री की व्यवस्था करेगा। बनावटी खाद की मांग उसके उत्पादन से कहीं अधिक है। इसलिये बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये खाद के कई और कारखाने खोले जा रहे हैं। खाद के स्थानीय साधनों और हरी खाद के उपयोग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सात राज्यों के चुने हुए जिलों में भरपूर खेती का कार्यक्रम चालू किया गया है। इस वर्ष सभी राज्यों में फसल उत्पादन आन्दोलन शुरू किये गये हैं, जिनके साथ पंचायतों, सहकारी समितियों और दूसरी ग्रामीण संस्थाओं का गहरा सम्बन्ध है। चार नये कृषि कालेज, दो पशु चिकित्सा कालेज और कुछ कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी तीसरी योजना में शामिल है।

उत्पादन और योजनाओं की विभिन्नता की दृष्टि से औद्योगिक पैदावार में भी काफी वृद्धि हुई है। लोहे और इस्पात, मशीनरी, बिजली के सामान और बनावटी खाद की पैदावार में पिछले वर्ष की अपेक्षा महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हमें आशा है कि १९६१-६२ में लक्ष्यों की प्राप्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होगी।

फिर भी आत्मसन्तोष और प्रयत्नों की ढिलाई के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी बहुत सी मुश्किलें और कठिनाइयां हैं, जैसे यातायात और कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में। निःसंदेह तीव्र आर्थिक विकास ही इन कठिनाइयों का कारण है।

योजना में दिये गये कार्यक्रम को कार्यरूप देने के लिये दृढ़ प्रयत्न जरूरी हैं और यह तभी हो सकता है यदि हम मितव्ययिता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखें और समय तथा प्राथमिकता की सूची का भी खयाल रखें। ये सब बातें मेरी सरकार के ध्यान में हैं और इन्हीं के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों पर पार पा सकते हैं।

मेरी सरकार ने भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर में लोहे के कारखानों के विस्तार तथा बोकारो में कच्चा लोहा और इस्पात का मिला जुला कारखाना और दुर्गापुर मिश्रित इस्पात का कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है।

तीसरी योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा कर हमने नौ करोड़ सत्तर लाख टन किया है, जिसे प्राप्त करने के लिये हमें इस उद्योग का योजना-बद्ध विकास करना है। सार्वजनिक खण्ड (Public Sector) में अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी और रूस की सहायता से बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है। कोयले के उत्पादन में निजी खण्ड अपनी विदेशी मृदा की जरूरतों को पूरा करने के लिये

विश्वबैंक द्वारा दिये गये ढाढ़े तीन करोड़ डालर के ऋण को उपयोग में ला सकेगा ।

नेवेली में पिछले वर्ष के अगस्त महीने में लिगनाइट की परतें दिखाई पड़ी थीं । लिगनाइट के प्रयोग से चलने वाला पहला बिजली का कारखाना आशा है शीघ्र ही काम करने लगेगा ।

गुजरात में अंकलेश्वर में तेल के उत्तम और लाभदायक साधन प्राप्त हुए हैं । नूनमाटी में तेल शोधक कारखाना इस वर्ष जनवरी में चालू हो गया था । इसके अतिरिक्त बीस लाख टन क्षमता का ऐसा ही कारखाना गुजरात में स्थापित करने की योजना है ।

आयात में कमी और निर्यात में कुछ वृद्धि के कारण गत बारह महीनों की अपेक्षा हम अपने व्यापार सम्बन्धी घाटे को ३६४ करोड़ से घटा कर २१८ करोड़ कर सके हैं । निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में अपने सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप मेरी सरकार निर्यात वस्तुओं की सूची में नयी चीजें जोड़ सकी है और नयी मंडियां ढूँढ सकी है । निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार ने कुछ नये प्रोत्साहन भी दिये हैं । यद्यपि गत वर्ष निर्यात व्यापार में वृद्धि केवल ३४ करोड़ रुपये की ही हुई है, इस बात से हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमारे व्यापार सन्तुलन का रुख अब अनुकूल है ।

औद्योगिक सम्बन्धों के मुद्धार के लिये १९५८ में ऐच्छिक आधार पर जो अनुशासन नियमावली बनाई गई थी उसका अधिकाधिक पालन किया जा रहा है, और इससे बहुत से ऐसे झगड़ों का निपटारा किया जा सका जो अन्यथा किसी एक पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही का कारण बन सकते थे । ऐच्छिक आधार पर औद्योगिक कारखानों में जो सम्मिलित प्रबन्ध-समितियां स्थापित की गई थीं उनके काम से यह प्रमाणित होता है कि

पूर्ण विचार-विमर्श से औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार और उत्पादन में वृद्धि होती है ।

प्रगतिशील खेती और ग्राम सुधार के लिये पंचायतीराज और सहकारिता की उन्नति और विकास अत्यन्त आवश्यक हैं । इस दिशा में मेरी सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप आठ राज्यों में ग्राम स्वशासन का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है और अनुमान है कि देश की ६५ प्रतिशत जनसंख्या इस सुधार के अन्तर्गत आ गई है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेरी सरकार ने ६ से ११ साल तक की उम्र के सब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की है । यह संख्या देश के कुल स्कूल जान वाले लड़कों का ६० प्रतिशत और लड़कियों का ६२ प्रतिशत है और ६—११ आयु के कुल बच्चों की संख्या का ७६ प्रतिशत है । स्कूलों में बच्चों की हाजिरी को अनिवार्य बनाने के लिये राज्यों की सरकारों को विधान स्वीकृत करने का मुद्दाव दिया जायगा ।

तिरुपति में केन्द्रीय संस्कृत परिषद् से आशा है आगामी वर्षों में संस्कृत के अध्ययन का विस्तार होगा । यह परिषद् संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित विशेष विषयों में अनुसन्धान भी करेगी ।

इंजीनियरिंग और टेक्नोलौजी के क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की मांग बराबर बढ़ रही है । इसे पूरा करने के लिये मौजूदा संस्थाओं का विस्तार और देश के विभिन्न भागों में नयी संस्थाओं का स्थापन किया जायगा ।

गरीब किन्तु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सहायता के लिये बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है ।

छूत की बीमारियों के उन्मूलन के लिये आवश्यक कदम उठाने को प्राथमिकता देना

मेरी सरकार की नीति है। इसके परिणाम-स्वरूप मलेरिया का लगभग उन्मूलन हो चुका है और क्षय रोग तथा गुन्तेन्द्रिय रोगों पर व्यापक नियन्त्रण किया जा सका है। देश भर से चेचक के उन्मूलन के कार्यक्रम को भी मेरी सरकार ने हाल ही में चालू किया है।

अभी तक हमारे अधिकांश ग्रामों में पीने के शुद्ध पानी की जो कमी है, उसे दूर करने के लिए स्वीकृत ग्रामीण योजनाओं का ५० प्रतिशत तक अनुदान के रूप में और शहरी इलाके में १०० प्रतिशत तक ऋण के रूप में सरकारी सहायता के तौर पर दिए जायेंगे।

सिंचाई की व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नर्मदा योजना द्वारा, जो ४३ करोड़ रुपये की है और जिसका उद्घाटन अप्रैल १९६१ में किया गया था, १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और उससे ५ लाख किलोवाट बिजली प्राप्त होगी।

राजस्थान नहर व्यवस्था की पहली नहर का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने गत अक्तूबर में किया था। जब यह नहर पूर्ण हो जायगी और प्रयोग में आने लगेगी, इसके द्वारा राजस्थान की मरुभूमि भारत के सब से बड़े धान्यागार में परिवर्तित हो जायगी।

मालदा होकर सिलीगुड़ी तक बड़ी लाइन के निर्माण से कलकत्ता और उत्तरी बंगाल में फिर से रेल सम्बन्ध स्थापित हो गया है, जो विभाजन के कारण टूट गया था। पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में चालू ७०० किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हो गया है।

गत वर्ष दो महत्वपूर्ण शताब्दियां राष्ट्रीय विमान पर मनाई गईं। टैगोर शताब्दी के सम्बन्ध में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी में विश्व भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भाग लिया। सभी राज्यों की राजधानियों

में टैगोर रंगमंच की स्थापना इस शताब्दी कार्यक्रम का अंग है।

भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी अपनी शताब्दी मनाई और उसके द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय एशियाई पुरातत्व सम्मेलन ने संसार के विभिन्न भागों से विद्वानों को आकृष्ट किया। दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी ने हमारी सभ्यता के अटूट ऐतिहासिक क्रम को लोगों के सामने चित्रित किया और हमारे अतीत को खण्डहरों और जीर्ण अवशेषों की कहानी न बता कर उसे राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा के स्रोत का रूप दिया।

चीन के साथ भारत के उलझे हुए सम्बन्ध अभी तक सुलझे नहीं हैं। अधिकारियों की रिपोर्ट, जो मेरी सरकार ने १९६१ में संसद् के सामने रखी थी, अभी तक चीन में प्रकाशित नहीं हुई है।

१९५४ की हिन्द-तिब्बती संधि की अवधि २ जून १९६२ को समाप्त होती है। चीनी लोकतन्त्र सरकार ने इस संधि के स्थान में नई संधि के लिये बातचीत का सुझाव भेजा है। इसके उत्तर के रूप में मेरी सरकार ने उनसे आग्रह किया है कि हमारे पड़ोसी अपनी आक्रमणात्मक नीतियों को छोड़ दें जिससे कि पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर शांति का वातावरण फिर से स्थापित किया जा सके।

जैसा कि संसद् को विदित है, कांगों में संकट के समय मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्रों की सहायता के लिये पर्याप्त सैनिक दल भेजने का निश्चय किया था, यद्यपि ऐसा करना हमारे लिये भार-स्वरूप था और अभी भी है। हमारे सैनिकों और अफसरों ने उल्लेखनीय वीरता, अनुशासन, संयम और सबसे बढ़ कर सद्भावना का परिचय दिया है। संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारियों ने ही नहीं बल्कि सभी देशों के नागरिकों ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। निजी आवश्यकताओं की दृष्टि से हम

इन सैनिकों को घर वापिस बुलाना चाहेंगे, किन्तु मेरी सरकार महसूस करती है कि वे आवश्यक काम जिनके लिये भारतीय सैनिक बाहर भेजे गये थे अभी अधूरे रहते हैं और इसलिये जो सहायता हमने दी है उसे जारी रखना मेरी सरकार ने मंजूर किया है, यद्यपि हमारे जवानों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। जो लोग बहुत समय से अफ्रीका में हैं उनकी बदली के लिये मेरी सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं। मेरी सरकार को इस बात से भी संतोष हुआ है कि इस मामले में पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच संयुक्त राष्ट्र में सहयोग के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे हैं।

मेरी सरकार के लिए यह भारी संतोष और मुख का विषय है कि अल्जीरिया में स्वाधीनता के आधार पर समझौते की ओर कदम उठाये गये हैं। हिंसा के कारण वहां जान का भारी नुकसान हो रहा है और उससे मेरी सरकार को बहुत क्षोभ हुआ है और इसीलिए वह अल्जीरिया और दि-गौल के पारस्परिक प्रयत्नों के सफल परिणाम की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। मेरी सरकार बार-बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि शांतिपूर्ण समझौते का एकमात्र आधार अल्जीरियन लोगों की स्वाधीनता है और स्थायी शांति अहिंसात्मक शांतिपूर्ण उपायों द्वारा ही स्थापित हो सकती है।

भारत को १८ राष्ट्र निःशस्त्रीकरण समिति का सदस्य चुना गया है। जिन नीतियों का इस समझौते में अनुसरण किया जायेगा और इस दिशा में हमने अभी तक जो योगदान दिया है उससे परिस्थितियों के सुलझने में सहायता मिलेगी, एक शांतिपूर्ण देश के रूप में और संसार में शान्ति के लिये उत्सुक क्षेत्रों के विस्तार में, संभव है, हम इस समझौते में

भाग ले कर शांतिपूर्ण समझौते और पारस्परिक मेल-मिलाप की भावना को बढ़ावा दे सकें, इस आशा से मेरी सरकार ने इस कठिन दायित्व को स्वीकार किया है। इस बीच में मेरी सरकार सभी दिशाओं में संसार भर में तनाव की भावना को कम करने के लिये भरसक प्रयत्न करेगी। मेरी सरकार को आशा है कि निःशस्त्रीकरण संबंधी बातचीत, कठिनाइयों के बावजूद, हमें युद्ध-विहीन विश्व की ओर ले जायेगी, जो हमारा ध्येय और नीति है।

जनीवा में होने वाले लाओस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग में मेरी सरकार बराबर भाग ले रही है। हम बराबर इस नीति को अपनाते रहे हैं कि लाओस की समस्या को राष्ट्रीय स्वाधीनता और वहां के लोगों तथा सरकार को सभी सम्बद्ध राष्ट्रों द्वारा आवश्यक तटस्थता की नीति का अवलम्बन करने की पूर्ण स्वाधीनता के आधार पर सुलझाया जा सकता है। यद्यपि यह समस्या अभी हल करनी रहती है, इस बात के लक्षण दिखाई देते हैं कि सुविख्यात राजनीतिज्ञ राजकुमार सुवन्नफूम के प्रधानमन्त्रित्व में इन सिद्धान्तों के आधार पर लाओस सरकार का निर्माण किया जा सकेगा। शान्ति के हित में हम वियेतनाम और कम्बोडिया के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग में बराबर भाग ले रहे हैं।

मेरी सरकार गाजा में संयुक्त राष्ट्रीय आपत्कालिक सैन्यदल में भी भाग ले रही है। इस दल में एक भारतीय टुकड़ी भी शामिल है।

स्वाधीन राष्ट्रों की पंक्ति में हम कई एक अफ्रीकी देशों का स्वागत करते हैं, जिनमें भूतपूर्व फ्रेंच कालोनियल अफ्रीका के बहुत से राज्य, भूतपूर्व अंग्रेजी भूभाग सीरालियोन और ब्रिटिश शासनाधिकार में भूतपूर्व मंडेडेड टेरेटरी टांगानिका शामिल हैं।

हमने सीरिया, सैनगल और टागानीका में अपने राजनयिक प्रतिनिधि नियुक्त किये हैं और कुवैत तथा उत्तर दक्षिण कोरिया के साथ, जिनके प्रतिनिधि हमारे देश का दौरा कर चुके हैं, व्यापार सम्बन्ध स्थापित किये हैं ।

स्वाधीन राष्ट्र के रूप में हम पश्चिमी सामोआ के उदय का स्वागत करते हैं ।

अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों के सम्बन्ध में मेरी सरकार ने सोवियत संघ के साथ सन्धि की है ।

सोवियत संघ के राष्ट्रपति, मलाया के सम्राट और सम्राज्ञी, नेपाल के सम्राट महेन्द्र, अर्जन्टाइना के राष्ट्रपति फ्रोंडिजी, पोलैंड के राष्ट्रपति ज्वादस्की, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और संयुक्त अरब राष्ट्र के उपराष्ट्रपति, डेन्मार्क, हंगरी, जापान, ट्रिनीदाद और बर्मा के प्रधान मंत्रियों ने भारत की यात्रा की और हमारे प्रधान मंत्री के साथ पारस्परिक हितों के विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में बातचीत की । फ्रांस के परराष्ट्र मंत्री और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सेक्रेटरी आफ स्टेट भी भारत आये और उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री से बातचीत की ।

हिन्द-पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार के लक्षण दिखाई नहीं दिये हैं । हमने पाकिस्तान सरकार के साथ "युद्ध नहीं" सन्धि पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दोहराया । हाल में पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा परिषद् से कश्मीर के प्रश्न पर विवाद करने के लिये प्रार्थना की, यद्यपि उन्होंने अपनी सेनाओं को हटा ले । और युद्ध-बन्दी रेखा के दूसरी तरफ हिंसात्मक गतिविधि बन्द करने और कश्मीर के अन्दर शान्ति-विरोधी शक्तियों की सहायता न करने सम्बन्धी उन समझौतों पर जो उन्होंने हमारे साथ तथा संयुक्त राष्ट्र के साथ किये थे किसी भी प्रकार न अमल किया है और न उन के प्रति कोई आदर दर्शाया है । किन्तु सुरक्षा परिषद् ने पाकिस्तान की प्रार्थना पर विचार स्थगित रखा है ।

जैसा कि संसद् जानती है, १४ वर्षों तक धैर्य-पूर्ण बातचीत और प्रतीक्षा के बाद हमारे देश की भूमि पर स्थापित पुर्तगाली उपनिवेशवाद की समस्या को मुलझाने का पुर्तगाल के मित्रों को पूर्ण अवसर दे चुकने के बाद, भारत सरकार को शान्ति के हित में, भारत की एकता के हित में और देश में अशोध्य जनमत के अनुसार देश की भूमि पर पुर्तगाली उपनिवेशवाद का अन्त करने के लिये कार्यवाही करनी पड़ी । पुर्तगाल द्वारा नग्न हिंसा, जिसमें हमारे व्यापारी बेड़े पर गोली चलाना, हमारे देशवासियों की हत्या करना और हमारी भूमि पर आक्रमण करना भी शामिल है, इन कार्यवाहियों के कारण यह समस्या भडक उठी । यद्यपि कुछ देशों ने भ्रान्तिपूर्ण आलोचना की है, फिर भी संसार के अन्य राष्ट्रों ने हमारी कार्यवाही की प्रशंसा की है, और निश्चय ही सब देशों की जनसंख्या ने पुर्तगाली उपनिवेशवाद का संसार के कम से कम एक भाग में अन्त का स्वागत किया है ।

आप सब संसद् सदस्यों के समान ही मुझे भी इस बात की खुशी है कि गोआ-सम्बन्धी कार्यवाही लगभग रक्तपात के बिना, और जहां तक वहां की गैरसैनिक जनसंख्या का सम्बन्ध है, जिसमें हमारे देशवासी और अन्य लोग भी शामिल है, पूर्ण रूप से हिंसा के बिना की जा सकी । गोआ पर सिविल कानून के अन्तर्गत मिलिट्री गवर्नर का शासन है और भारतीय संघ के अविभाज्य अंग के रूप में उन भूभागों की स्थिति को वैधानिक रूप देने के लिये संसद् के इस सत्र के सामने एक विधेयक रखा जायेगा । हमने गोआ की जनता और संसार को बार बार आश्वासन दिया है कि ऐतिहासिक कारणों से जो विशेषता इस प्रदेश को प्राप्त है, उसका हमारे संविधान के मौलिक तत्वों की सीमा में सदा आदर किया जायेगा और जो भी परिवर्तन हो वह रचनात्मक तथा निर्विघ्न होगा । पहले के पुर्तगाली उपनिवेश के लोगों को हमारे संविधान के आधारभूत अधिकारों और मौलिक सिद्धान्तों

के अनुसार संरक्षण प्राप्त है। मेरी सरकार इस विषय पर इसी संसद् के इसी सत्र में एक विधेयक पेश करना चाहती है।

मेरी सरकार ने भूटान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में सत्रह करोड़ रुपये की सहायता देना स्वीकार किया है। स्वयं भूटान की सरकार के तथा सीमा-सड़क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यातायात को सबसे प्रमुख स्थान मिल रहा है। आशा की जाती है कि इस वर्ष भूटान में मोटर यातायात स्थापित करना सम्भव होगा। मेरी सरकार को इस बात से खुशी है कि इन सभी विकास कार्यों में भूटान की सरकार ने पहल की है जिसमें मेरी सरकार पूरा सहयोग दे रही है।

आर्थिक चालू वर्ष १९६२-६३ के लिये भारत सरकार का अनुमानित आय-व्यय का व्यौरा इस वर्ष के एक भाग के व्यय का अधिकार देने के लिये आपके सामने पेश किया जायेगा।

संसद् का यह अधिवेशन बहुत ही छोटा होगा और इसलिये केवल आवश्यक विधान ही इस सत्र में हाथ में लिया जायेगा। कुछ अध्यादेश, जो पिछले सत्र के बाद जारी किये गये थे, संसद् के सामने रखे जायेंगे।

ग्राम चुनाव अब पूरे हो चुके हैं। संसद् के सदस्यगण, मैं भी आपकी खुशी में अपनी प्रसन्नता की यह ध्वनि मिलाना चाहूंगा कि इतना बड़ा मतान्तरिक शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित और हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार सम्पन्न हुआ है। हमने अपने लिये एक उदाहरण स्थापित किया है और अप्रत्यक्ष रूप से लोक-तन्त्रात्मक शासन प्रणाली में संसार की आस्था को बढ़ाया है।

चुनाव के परिणामस्वरूप मेरी सरकार को अपनी आन्तरिक तथा विदेश नीतियों के प्रति विशेष विश्वास प्राप्त हुआ है और इस बात का उसे फिर से अधिकृत आदेश मिला है

कि दूर गांवों में भी ग्राम चुनावों के आधार पर जनतन्त्रात्मक पद्धति के द्वारा लोक-तन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के लिये फिर से वह कठिन अध्यवसाय के साथ और तेजी से प्रयत्नशील हो ताकि लोकतन्त्र एक वास्तविकता बन जाय। राष्ट्रीय एकता और तटस्थ नीति द्वारा विश्वशान्ति, शान्तिपूर्ण तरीकों से समस्याओं का निराकरण, तनाव कम करने और समझौते द्वारा समस्याओं को हल करने की नीतियों का राष्ट्र ने पुनः समर्थन किया है। यह पुनर्विश्वास और आस्था जो लोगों ने मेरी सरकार के प्रति और उसकी आन्तरिक तथा विदेश नीति के प्रति, जिसे अनेक बार संसद् का समर्थन प्राप्त हो चुका है और चुनाव से पहले जिसका देशव्यापी विवेचन हो चुका है, सरकार की नीतियों को सुदृढ़ बनाती है और इसके द्वारा मेरी सरकार पर राष्ट्रीय आदेश के रूप में यह दायित्व आता है कि वह दृढ़ता से इन नीतियों को कार्यान्वित करे।

संसद् के सदस्यगण, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे विश्वास है कि आपमें से जो लोग पुनः संसद् सदस्य के रूप में यहां नहीं आयेंगे, वे राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य में लगे रहेंगे। यह कार्य हमारे जनतन्त्र की प्रगति, समाजवादी समाज के निर्माण तथा संसार में शान्ति की स्थापना के लिये बहुत आवश्यक है। आप में से जिन्हें इन वैधानिक प्रवृत्तियों को चालू रखने के लिये जनमत का आदेश मिल गया है, वे अपने कठिन किन्तु रचनात्मक और राष्ट्र-निर्माण के फलदायी प्रयास को जारी रखने के लिए उन्हीं के साथ शामिल हो जायेंगे जो पहली बार संसद् में आ रहे हैं।

थोड़े ही समय बाद एक नई संसद् का उद्घाटन होगा और पूर्व वर्षों की तरह ही किन्तु नवीन उत्साह और नवोदित शक्ति के साथ आप तथा वे सभी हमारे संविधान के

मौलिक सिद्धान्तों की स्थापना और उन्हें अधिकाधिक कार्यरूप देने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे ।

वे मौलिक सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतन्त्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता,

सभी नागरिकों के बीच भ्रातृभाव को

प्रोत्साहन जिसके द्वारा व्यक्ति की

गरिमा और राष्ट्र की एकता

मुनिश्चित हो ।

ये सिद्धान्त अपने पूर्ण अर्थों समेत हाल के शिक्षाप्रद और महान चुनावों के समय मेरी सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के सामने रख दिये गये थे ।

आप जहां कहीं भी हों, मैं आपकी सफलता और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं ।

(Text of the President's Address in English)

Members of Parliament, this is the last occasion that I shall be addressing you in this Parliament.

Members of the Lok Sabha, you are about to end your five year tenure of membership of your House. A new Lok Sabha will meet very shortly after the conclusion of your present labours. Many of you have been returned by the people to serve the country again. Some of you will cease to be Members of Parliament consequent on the dissolution of the Lok Sabha and the elections. I would like to take this opportunity to congratulate all of you and to convey to you the gratitude of the nation for your dedicated service as Members of Parliament. I have also no doubt that wherever your field of work may be hereafter you will remain dedicated to the great task of nation-building and that your wisdom and experience

will continue to be engaged in the service of our country and people.

Members of Parliament! When I addressed you last, our Third Five Year Plan with its larger perspectives and higher targets was under preparation. The Plan has now been well launched. The experience of previous plans, the momentum that they have generated, and the greater nation-wide understanding and appreciation of planned effort in nation-building augur well for the success of this Plan and will take us nearer our goal—a self-sustaining economy capable of increasing and generating resources for larger and further development.

In spite of the heavy damage inflicted by floods in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mysore, Madras and Kerala, the agricultural yield for 1961-62 is encouraging. The development of agriculture has been accorded a high priority in the Third Five Year Plan. The aim has been not merely to achieve self-sufficiency in foodgrains but to step up the production of commercial crops as well as to ensure adequate supplies of raw material for our growing industries and to help export to earn foreign exchange. The overall index number of agricultural production rose to 139.1 in 1960-61, compared to 128.7 in 1959-60, thereby showing an increase of 8.1 per cent. This increase was shared both by foodgrains and commercial crops. Compared to the index for 1955-56, the base year of the Second Five Year Plan, the overall index of production for 1960-61 was higher by about 19.1 per cent.

By soil conservation measures and dry farming practices some 33 million acres of land will be brought under improvement. Minor irrigation schemes will bring 12.8 million acres of additional land under cultivation during the Third Plan. My Government have decided to set up an Improved Seed Corporation to organise on a nation-wide scale the production, distribution and marketing of

seeds of higher yield and disease-resisting quality. The demand for fertilisers far exceeds supply. More fertiliser factories are therefore being set up to meet partly the increased needs. Local manure resources and the use of green manure are also being promoted.

An extensive Agricultural District Programme has been put into operation in selected districts in seven States. Crop production campaigns have been launched in all States during the year. Panchayats, Co-operatives and other institutions in the village are closely associated in these campaigns. Four new Agricultural Colleges and two new Veterinary Colleges and more Agricultural Universities are to be established during the Third Plan.

Industrial production has registered considerable increase in volume and a greater diversity in categories of projects. The output in iron and steel, machinery, electrical goods and fertilisers has been significantly higher than last year. The attainment of targets and the increase in our national income in 1961-62 are expected to accord with those set out in the Plan.

There is, however, no room for complacency or any slackening in effort. There are considerable strains and stresses, as for example, in regard to transport and supplies of coal. These are no doubt due to the sharp rise in economic development.

A determined effort to implement the physical programmes as set out in the Plan would require care in regard to economy and efficiency and the endeavour to keep to time schedules and priorities, all of which are the continuing concern of my Government, will alone help the country to overcome these obstacles.

My Government have decided to expand the steel plants at Bhilai, Rourkela and Durgapur and to establish a new integrated iron and steel

plant at Bokaro, and a new alloy steel plant at Durgapur.

The augmented target for coal production of 97 million tons in the Third Plan calls for plans of development in this industry. Major schemes are being launched in the public sector with assistance from the U.S.A., France, Poland, West Germany and the U.S.S.R. The private sector in coal will be able to utilise a 35 million-dollar loan from the World Bank to meet its foreign exchange requirements.

At Neyveli, the lignite bed was exposed in the August of last year. The first thermal power station using lignite is expected to be commissioned soon.

In Gujarat at Ankleshwar, appreciable and gainfully exploitable sources of oil have been found. In addition to the refinery at Nunmati which went on stream in January 1962, it is also proposed to establish a refinery of two million ton capacity in Gujarat.

Our trade deficits show a welcome decline from 364 crores to 218 crores as compared with the previous twelve-month due to the fall in imports and a slight rise in exports. My Government by their continuous and strenuous endeavours to promote exports have added new items of export and newer markets, and established new incentives to augment export trade. While the increase in export is a moderate Rs. 34 crores worth in the year past we may justifiably feel encouraged that a favourable trend in our trade balance can now be a feature of our economy.

The Code of Discipline in industrial relations evolved in May 1958 on a voluntary basis is being increasingly observed and has resulted in the settlement of a large number of disputes which might otherwise have led to direct action by one side or the other. Joint Management Councils in industrial undertakings set up on a

voluntary basis have shown that the effective consultation which they promote has led to improved industrial relations and increased productivity.

The development and growth of Panchayati Raj and co-operation are integral to progressive agricultural and rural development. The efforts of my Government in this direction have already resulted in large scale extension of village self-government in eight States and it is estimated that this covers 65 per cent. of the country's population.

My Government have made provision for education for all children in the age group of 6—11 during the Third Plan which will enable 90 per cent. of the boys and about 62 per cent. of the girls to be at school making a total of 76 per cent. of the total population of all children in the age group 6—11. Legislation to make attendance of children compulsory will be recommended to various State Governments.

The study of Sanskrit is expected to make considerable advance in the next few years by the establishment of a Central Sanskrit Institute at Tirupati which will also conduct research in specialised branches of Sanskrit learning.

The demand for trained personnel in the fields of Engineering and Technology continues to grow. To meet this demand, apart from strengthening the existing institutions more institutes were set up in different parts of the country.

To assist poor but meritorious students a large number of scholarships have been instituted.

The policy of my Government accords priority in promoting measures for the eradication of communicable diseases. This has resulted in the near eradication of malaria and the widespread control of tuberculosis and venereal diseases. My Government have recently initiated a programme for the eradication of small-pox in the country.

To overcome the scarcity of pure drinking water which exists in the majority of our villages, assistance will now be made available to the extent of 50 per cent. on a grant-in-aid basis on approved rural schemes and on a 100 per cent. loan basis in regard to urban schemes.

Irrigation has made significant advances. The 43 crore Narmada Project inaugurated in April 1961 will irrigate one million acres of land and yield an effective half a million kilowatts of power.

The first channel of the Rajasthan Canal system was opened by the Vice-President in October last. This canal when completed and operated will convert the deserts of Rajasthan into the largest grain bowl of India.

The new broad-gauge line to Siliguri via Malda has re-established a broad-gauge rail connection between Calcutta and North Bengal, which had been severed by the Partition. Over 700 route kilometres of railway lines serving the industrial East have been electrified.

Two important centenaries were celebrated during the year and nationally observed. The Tagore Centenary attracted distinguished writers from all over the world to its International Literary Seminar. The Centenary programme includes the erection of a Tagore Theatre in every State Capital.

The Archaeological Survey of India also celebrated its centenary which attracted to its International Conference of Asian Archaeology savants from different parts of the world. The exhibition in Delhi made live to our people in graphic form the historic continuity of our civilisation and made the past not a story of ruins and fossils, but a source of national pride and inspiration.

India's uneasy relations with China remain unsolved. The Officials' Re-

port, which was placed by my Government before Parliament in 1961, has not yet been published in China.

The Indo-Tibetan Agreement of 1954 is due to expire on the 2nd of June 1962. The Government of the People's Republic of China have offered to negotiate a new Agreement to replace the 1954 Agreement. My Government responding by way of reply, have asked for a reversal of the aggressive policies pursued by our neighbour and for the restoration of a climate of peace on the basis of the strict observance of the Five Principles.

In the Congo, as Parliament is aware, my Government at a critical period took a crucial decision: to send adequate armed forces to assist the United Nations, although it was and continues to be a great strain upon us to do so. Our men and officers have behaved with remarkable bravery, discipline and restraint and above all, with understanding. They have received the plaudits of nationals of all countries not to speak of the United Nations authorities. While we would like to bring these troops home in view of our own necessities, my Government feel that the essential tasks for which India sent troops remain unfulfilled and, therefore, have agreed to continue the assistance which was given, even though our men are working in difficult conditions, and have taken the necessary steps for the relief of personnel that have been too long in Africa. My Government are also gratified that in this matter there are some indications of a co-operative United Nations outlook between the Western Powers and the Soviet Union.

My Government note with great relief and gratification the moves towards reconciliation on the basis of the independence of Algeria. They are deeply distressed at the continued violence which is taking a heavy toll of life, and they await with expectation the successful outcome of the present Algerian-de Gaulle efforts. My Government have repeatedly pro-

claimed their position that the only firm basis for a peaceful settlement is the independence of the Algerian people, and enduring peace is best brought about by peaceful methods.

India has been elected to the 18-Nation Disarmament Committee. My Government have accepted this onerous role in the hope that the policies to be pursued and the contribution which we have made in the past may help healthy developments, and that as a peace-minded country and with the growth of peace areas in the world India may be able to participate and assist the processes of reconciliation and peaceful settlement. Meanwhile my Government will use their best efforts in every direction to lower tensions in the world. My Government hope that the Disarmament negotiations will, in spite of difficulties, lead to a warless world which is our aim and policy.

My Government continue their participation in the International Conference on Laos at Geneva and the International Commission for Supervision and Control. We have adhered to the policy that the Laotian problem can only be solved on the basis of national independence and of the full freedom of the people and Government of Laos to maintain neutrality which should be assured by all concerned. Although the problem awaits solution the indications are that we may look forward to a Laotian Government wedded to these principles under the Premiership of that distinguished statesman, Prince Souvanna Phouma. We are continuing to participate in the International Commissions for Supervision and Control in Vietnam and Cambodia in the interests of peace.

My Government also continue their participation in the U.N. Emergency Force in Gaza, to which India has contributed a contingent.

We welcome to the comity of independent nations several African States including many States in the former French Colonial Africa, Sierra

Leone, formerly British, and Tanganyika, a former Mandated Territory under British Administration.

We have appointed diplomatic representatives to Syria, Senegal and Tanganyika, and established trade relations with Kuwait and with North and South Korea whose representatives also visited this country.

We welcome the emergence of Western Samoa as an independent country.

My Government have concluded an agreement with the Soviet Union on the Peaceful Uses of Atomic Energy.

The President of the Soviet Union, the King and Queen of Malaya, King Mahendra of Nepal, President Frondizi of Argentine, President Zawadski of Poland, the Vice-Presidents of the U.S.A. and the UAR, the Prime Ministers of Denmark, Hungary, Japan, Trinidad and Burma paid visits to India and had discussions with my Prime Minister on a variety of topics of mutual interest. The Foreign Minister of France and the Secretary of State of the United States also visited India and had discussions with my Prime Minister.

Indo-Pakistan relations have shown no signs of improvement. We have repeated our offer to the Pakistan Government to sign a "No War" Agreement. The Pakistan Government requested the Security Council recently to debate the Kashmir issue again although they had not in any way implemented or honoured the agreements which they made with us and the United Nations in regard to withdrawal of forces, etc., or stopped aggressive activities across the cease-fire line or aiding subversion inside Kashmir. The Security Council has, however, deferred its consideration of the Pakistan request.

As Parliament is aware, after fourteen years of patient negotiations and waiting and giving an opportunity for the friends of Portugal to resolve the

problem of the Portuguese colonialism on our mainland, the Government of India, in the interests of peace, the unity of India and on account of the irresistible volume of public opinion in our country, had to take action to bring an end to Portuguese colonialism on the mainland. This issue was precipitated by acts of flagrant aggression by Portugal including firing upon our merchant shipping, the killing of our nationals and intrusion into our territory. While there has been ill-informed criticism from some countries, the rest of the world has applauded this action and indeed the populations of all countries appear to welcome the end of Portuguese colonialism in at least a part of the world.

I am very happy, as you Members of Parliament are, that the operation in regard to Goa was practically bloodless and certainly entirely so in regard to civilian populations including our compatriots and all others. Goa is administered by a Military Governor under civil law and legislation will be introduced in the present Parliament to regularise the position of these territories as integral part of the Union of India. We have however repeatedly assured the peoples in Goa and the world that the personality that this area has acquired as a result of history would be respected, within the limits of the fundamentals of our Constitution, and that any changes would be constructive and smooth. The people of the former Portuguese colony have the protection of the fundamental rights and the basic principles of our Constitution. My Government propose to submit a Bill to Parliament in this session on this matter.

My Government have agreed to help finance the first Five Year Plan for economic and social development in Bhutan to the tune of Rs. 17 crores. Communications in this area are receiving priority consideration by the Bhutanese Government itself and under the Border Roads Development Programme. It is hoped that during

this year it will be possible to establish motor traffic in Bhutan. My Government are happy that the initiative for all these developments has been taken by the Bhutanese Government, in which my Government are co-operating.

A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1962-63 will be laid before you for the purpose of passing votes on account authorising expenditure for a part of that year.

As this session of Parliament will be a very brief one, only essential legislation will be taken up during this session. Some Ordinances which have been promulgated since the last session will be placed before Parliament.

General Elections are now complete. Members of Parliament, I would like to echo your sense of rejoicing that this vast democratic exercise has been peaceful, orderly and in accordance with our constitutional processes. We have set an example to ourselves and indirectly assisted the confidence in the world in the institution and the processes of Parliamentary Government.

As a result of the elections my Government have received a significant vote of confidence in their internal and external policies and a renewed mandate to strive strenuously and with speed for the establishment of a democratic socialist society and for the extension of the democratic institutions and processes on the basis of universal suffrage to the remotest of our villages, making democracy a reality. The policies of national integration and world peace through non-alignment, peaceful approach to problems, lowering of tensions and negotiated settlements have also received the endorsement of the nation. This renewed assurance and confidence placed by the great majority of our people in my Government and

the avowal of their support for policies, internal and external, that have been repeatedly endorsed by Parliament and widely discussed by the country prior to the election reinforce these policies and place on my Government a nationally mandated obligation and added strength to implement these policies.

Members of Parliament, I now bid you farewell. I feel confident that those of you who do not return here as legislators, will pursue useful and constructive roles in various fields of national activity so essential for the advancement of our democracy and for the building of our socialist society and for the furtherance of peace in the world. Those of you who have received the mandate of the electorate to continue your legislative activity will join with others who will come here for the first time to continue the arduous but constructive and fruitful labours for nation-building.

In a short time a new Parliament will be inaugurated and as in years past, but with renewed vigour and galvanised strength, you and they can strive for establishment and further implementation of the principles of our Constitution, namely:—

Justice, social, economic and political;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;

Equality of status and of opportunity;

And to promote among all the citizens

Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation.

These have been fully placed by my Government before our nation during the vast and educative process of our election and in its full implications.

I wish you all success and good fortune wherever you may be.